plemented alongwith the progress it has achieved during the last three years;

(b) the mode of its implementation; and

(c) the number of illiterates in rural and urban areas separately benefited from this programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) The Adult Education Programme is being implemented in all the States and Union Territories. A statement showing the adults in the group 15—35 covered under the programme during the last three years is attached. (Annexure-I).

(b) Various agencies such as the State Governments, voluntary organisations, Nehru Yuvak Kendras, and Universities/ Colleges are associated in the implementation of this programme.

(c) A statement showing enrolment by rural/urban areas during 1981-82 is laid on the Table of the House. [*Pleaced in Library. See* No. Lt. 5555/82]

अंग्रेजी और हिन्दी में भेजे गये पत्र

3028. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1982 की पहली छमाही के दौरान उनके मंत्रालय में 'ए' और 'बी' क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य को कुल कितने मूल पत्र आदि भेजे हैं उनमें से कितने पत्र अंग्रेजी और कितने हिन्दी में लिखे गए थे;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 में यह व्यवस्था है कि इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में लिखे जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा मूल पत्र व्यवहार के बारे में राज्यवार आकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) राज्यों का 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण राजभाषा (संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के अंतर्गत किया गया है न कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन। राजभाषा 1976 और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1982–83 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्रों के राज्यों के साथ मूल पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाना चाहिये। रेल मंत्रालय को अभी यह लक्ष्य प्राप्त करना है।

(घ) स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गये जिनमें उल्लेखनीय है :—

(1) हिन्दी के कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है।

(2) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जाती है।

(3) ईशू और रोनियो अनुभागों में चेक प्वांइट बनाए गए हैं और वहां निगरानी रखी जाती है